आखर हिंदी पत्रिका; e-ISSN-2583-0597 खंड 4/अंक 3/सितंबर 2024

Received: 31/09/2024; Accepted: 2/09/2024; Published: 26/09/2024

लेख

किसानों की महागाथा

डॉ. डिम्पल जेनिफ़र फ़ेर्नांडिस
हिन्दी
विभागाध्यक्षा
संत फ़िलोमिना कॉलेज,
पुत्तुर-५७४२०२ कर्नाटक
मो.नं : ९८४४९०५०९८

डॉ. डिम्पल जेनिफ़र फ़ेर्नांडिस, **किसानों की महागाथा**,आखर हिंदी पत्रिका खंड 4/अंक 3/सितंबर 2024, (241- 244)

कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्ता की रीढ माने जानेवाले किसान की स्थितिगति का चित्रण पस्तुत करने की छोटी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कोरोना महामारी के समय जब सब कुछ बन्द था तब भारत की अर्थव्यवस्था का एक स्तम्भ इस देश को स्थिरता और लडने की शक्ति प्रदान कर रहा था, वह खेत में खडा किसान था।

सदियों से ग्रामीण भारत की अर्थ व्यवस्था कृषि आधारित रही है और किसान हर दौर में हाशिए पर ही रहा है। मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक दौर से ही खेती व किसानी को श्रेष्ठ उद्यम माना जाता रहा है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पता चलता है कि प्राचीन काल से ही बडी बडी रियासतों की आर्थिक आधार कृषि और पशुधन ही रहा है। यह भी कडवी सच्चाई है कि अन्नदाता के नाम से विभूषित किसान सदैव उपेक्षित ही रहा। किसान या तो अशिक्षित है या फ़िर अल्पशिक्षित। उन्होंने किताब देखी है, विध्यालय का अर्थ समझते हैं, अक्षर से अपरिचित नहीं हैं मगर अफ़सोस कि वे किताब विध्यालय अथवा अक्षर का अद्वितीय लाभ अपने व्यक्तित्व के विकास में नहीं उठा सकते। बावजूद इसके, उनके पास ज्ञान है, मगर जीवन के संघर्षमय अनुभवों से। प्रतिदिन प्रतिपल बिछे हुए संघर्ष और श्रम की पाठशाला में पढते, दंड सहते, रोते और पास-फ़ेल होते हुए वह आत्मशिक्षित हुआ है। जीवन की कठिण हकीकतों की मिसाल है किसान।

कोविड १९ के आगमन से सारे सामाजिक बंधन टूट गये और जीवन के सभी क्षेत्र प्रभावित हुए। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो गईं। भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के देश के लिए इसका परिणाम बडा ही नुकसानदायक था। कोविड १९ के कारण हुए तालाबंदी के कारण कृषि

उपज की आपूर्ति- श्रृंखला में गडबडी ने किसान और उपभोक्ता दोनों को नुकसान पहुँचाया। लॉकडाउन ने न केवल देशभर में लोगों के आवागमन को सीमित कर दिया बल्कि नियंत्रण क्षेत्र, सामाजिक दूरी, यात्रा प्रतिबंध आदि नीतियों को भी लागू कर दिया। इन नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को प्रभावित किया।

कृषि ही एक ऐसी उम्मीद है जो अर्थव्यवस्था में नई जान फ़ूंकने का कार्य कर सकती है। लेकिन यह देश्व्यापी तालाबंदी किसानों के आर्थिक नुकसान का सबब बनी, विशेषकर सब्जी और फ़ल उत्पादक किसानों की मुसीबतें और बढ गईं। कृषि उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुँचाने की जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें परिवहन एक अहम कडी है। व्यापार और परिवहन एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लॉकडाउन में यही कडी कमजोर हो गई। बाजारों से जोडनेवाली कडियाँ टूट गईं। फ़ल व सब्जियाँ खेत में सड गईं।

कर्नाटक में खरबूजा, टमाटर, गोभी की खेती करनेवाले किसानों ने कहा कि कटाई के लिए कोई मजदूर न होने और इसे बाजार तक ले जाने केलिए परिवहन की कोई सुविधा न होने के कारण उनकी उपज को खेत में ही सडने के लिए छोड दिया गया था। कई टन उपज सूखे तालाब में फ़ेंखे गये, कई जगहों पर मवेशियों को चरने दिया गया। टमाटर और मिर्ची की फ़सल सडकों पर फ़ेंक दी गई। राज्य भर में कृषि उपज कम कीमतों पर बेची गई। कुछ स्थानों पर बाजार बंद होने से सारी उपज खराब व बर्बाद हो गई। केले, फ़ूल, टमाटर,धान,और बागवानी उत्पादों की खेती करनेवाले किसानों को बेहद नुकसान उठाना पडा।

ग्रामीण भारतीय जो अधिकतर असंघठित मजदूर हैं वे हर परिभाषा के हिसाब से गरीब हैं, उन्हें नियमित रोजगार नहीं मिलता। जब ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के मामले अधिक थे उनके लिए आर्थिक संकट और बढ गया। एक और समस्या श्रम संकट का भी था। ग्रामीण इलाकों में भी नौकरियों के जाने और बेरोजगारी बढने की बात सामने आई। किसानों और खेतिहार मजदूरों के संक्रमित होने के कारण ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला पर असर पडा। कोविड १९ का जो असर लोगों की आमदनी और अर्थव्यवस्था पर पडा है वह काफ़ी ज्यादा था। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य का बुनियादी ढाँचा वाकई नाजुक स्थिति में है। तालाबंदी के दौरान कई किसानों ने आत्महत्या भी की। अनेक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा के बावजूद भी किसान अपने अस्तित्व को कुचक्रों के षडयंत्र से बचा पाने में असमर्थ ही रहा है। किसानों के लिए सरकारी आश्वासन कभी न खतम होने वाले इंतजार में तब्दील हो चुके हैं। हताशा और विफ़लता ने उनके भीतर जीने की उम्मीद ही तोड दी।

खेतीबाडी में मजदूरों की संख्या काफ़ी कम होती है। कोरोना के समय मजदूरों की कमी के कारण ज्यादातर किसानों ने आधुनिक उपकरण/साधनों कि तरफ़ मुँह किया। यंत्र, मानव सामर्थ्य से ज्यादा काम करते हैं। इसमें सिर्फ़ एक बार निवेश करना होता है और यंत्रों को कई बार इस्तेमाल में ला सकते हैं, लाभ भी ज्यादा है ऐसा किसानों को लगने लगा। वे यंत्रों कि तरफ़ झुक गये।

कोरोना के बाद आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल बड गया है । नवीनतम वैज्ञानिक साधनों को अपनाकर वह खेती के कई तरीके सीख रहा है । शिक्षा के माध्यम से खेती में काफ़ी जागरूकता ला रहा है । कोरोना के बाद के समय में किसानों की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है, बेरोजगारी कम हुई है, जनजीवन बडे अच्छे से चल रहा है ।

किसानों की पीडा और उनके शोषण दमन का इतिहास सदियों पुराना है । प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ-सुखाड, जाडा-पाला, फ़सलों के रोग आदि से किसानों के पैदावर में नुकसान होने की बात पुरानी होने के बावजूद आज भी यह समस्या लगभग ज्यों की त्यों बनी हुई है । पशु पक्षियों द्वारा फ़सल को बर्बाद किये जाने के किस्से भी आम हैं । इतिहास गवाह है कि किसान हमेशा से सरकार के खिलाफ़ अपनी इन समस्याओं और शोषण के खिलाफ़ आवाज उठाते रहे हैं । यह और बात है की सरकार उनकी समस्याओं को लेकर कभी गंभीर नहीं हुई । अनाज का अच्छा उत्पादन भारत जैसे गरीब और अत्यधिक जनसंख्या वाले देश के लिए बहुत ही जरूरी है ।

किसानों में विभिन्न मौसमों , जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की स्थिति, जंगल की आग,जंगली जानवरों का हमला, सूखे और बाढ के कठोर विनाश के साथ जीवित रहने की क्षमता होती है । कर्नाटक में ज्यादातर बंदर और जंगली सुअर फ़सल खराब करते हैं लेकिन उन्हें मारना कानूनन अपराध है,इससे किसान बहुर परेशान हैं ।

हाली में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कर्नाटक का लक्ष्य २०२३-२४ तक किसानों की आय दोगुनी करनेवाला पहला राज्य् बनना है और इस संबंध में विशिष्ट रिपोर्ट तैयार करने केलिए किसानों की एक समिति का गठन किया जाएगा जिसे सरकार लागू करेगी । सरकार ने एक 'माध्यमिक कृषि निदेशालय' स्थापित करने का भी फ़ैसला किया है जो खाध्य संस्करण और सभी कृषि उत्पादों के संबंध में काम करेगी । कृषि विश्वविध्यालयों की मदद से बीज,कीट, और उर्वरक प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने और मिट्टी में पोषण स्तर में सुधार के संबंध में साथ ही कृषि, उध्यनिकी, रेशम उत्पादन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन सहित खाध्य एवं समस्त कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के संबंध में एक विशेष कार्यदल का गठन जिसे 'माध्यमिक कृषि निदेशालय' के नाम से जाना जाएगा ।

किसानों के व्यापक हित के लिए जरूरी है कि सूखाग्रस्त इलाकों में सरकार सालों भर जल के अपूर्ति का कार्य सुनिश्चित करे । हाल ही में हुए किसान आंदोलन में किसानों की जीत से उनके आत्मविश्वास और स्वाभिमान में वृद्धि हुई । पूरे देशवासियों के खून के अंदर एक नये किस्म की हरारत पैदा हुई है । आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि किसान अपने हितों के इस लडाई को आगे कैसा निर्णायक मोड देते हैं । सरकार को चाहिए की वह किसानों को उनकी पैदावर बढाने में मदद करे तथा उनके उत्पाद को उचित दर पर खरीददारी को सुनिश्चित करे । देश में जय जवान के साथ साथ जय किसान के नारे को पुनः प्रतिष्ठित करने की जरूरत है । किसानों की आय में वृद्धी होने का सीधा अर्थ है देश में खुशहाली और समृद्धि के एक नये दौर का आना ।

किसी भी आपदा के असली अदृश्य हीरो किसान ही हैं। किसान सच्चे कर्मयोद्धा हैं जो बारिश, सूखा, बाढ जैसे तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी उत्पादन को जारी रखते हैं। सभी बाधाओं के बीच जीवन जीना किसानों के खून में है। कुछ शहरी लोग सवाल करते हैं कि अगर खेती घाटे का सौदा है तो किसान छोड क्यों नहीं देते? इसका उत्तर भी बडा ही स्पष्ट है कि किसान मुनाफ़े जैसी छोटी सोच न रखकर खेती को जीवन जीने की कला मानते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी खेती जारी रखते हैं। लागत, आय, पूँजी, निवेश पर मुनाफ़ा या प्रति व्यक्ति आय सब विदेशी अवधारणा है। किसानों को जब तक लागत और परिश्रम के बराबर भी नकदी मिलती रहेगी तब तक किसान खेती करता रहेगा।

****